(ग) संसाधन मैत्री-स्तर पर आर्थिक क्षेत्रकों में आवंटित किए जाते हैं । किसी क्षेत्रक के भीतर कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के आवंटन के निर्धारण हेतु कोई मानक मापदंड नहीं है । बहरहाल, नौवीं योजना के एप्रोच पेपर में कार्यक्रमों और स्कीमों और परियोजनाओं के चयन के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का प्रस्ताव किया गया है :—

(1) वे स्कीमें जो दूसरी जनसंख्या के तुलना में गरीबी को अधिक लाभ पहुंचाने वाली है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(2) वे स्कीमें जो महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को पूर्ण जनसंख्या की अपेक्षा लाभ पहुंचाती हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(3) वे स्कीमें जो पिछड़े क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंचाने वाली हैं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(4) वे स्कीमें जो गैर-विस्थापनकारी शक्तियां प्रदान करने वाली और श्रम गहन है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(5) वे स्कीमें जो दीर्घकालीन मतन लाभ देती हैं, को उन स्कीमों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो परिवर्ती प्रकृति का थोड़ा सा अधिक लाभ पहुंचाती है ।

(6) वे स्कीमें जो उत्पादक परिसम्पत्तियों (वैचारिक परिसम्पत्तियां और पूर्ण आर्थिक परिसम्पत्तियां) के निर्माण में मदद करती है, को उन स्कीमों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो केवल आय बढ़ाने अथवा कल्याण में मदद करती है ।

(7) सेवानमुखी स्कीमें (बनियादी न्यूनतम सेवाओं की श्रेणी में आने वाली को छोड़कर) जिनके लिए उच्च स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपेक्षित है, को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ऐसी सेवाओं के वाणिज्यिक प्रचालन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(8) वे स्कीमें जो क्रमबद्ध सुधारों, विधायी ढांचे में परिवर्तन, संस्थानात्मक विकास, भागीदारी एप्रोच के संवर्धन और स्वशासन की पद्धति से उत्साहजनक वातावरण की अपेक्षा रखती है, को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

देश में विद्युत उत्पादन क्षमता

2608. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विद्युत उत्पादन की कुल क्षिमता कितनी है तथा इसकी आवश्यकता कितनी है ;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना-वधि के अंत तक देश की विद्युत आवश्यकता को पूरा कर दिया जाएगा ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य में कितना विदेशी निवेश होने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहेरेश्वर सबनूर) : (क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (सेवा प्रदायक सुविधा में) 84912.4 मे. वा. थी । वर्ष 1996-97 के दौरान 365.90 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो 413.49 बिलियन यूनिट की कुल ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में है ।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत के संवर्धित कार्यक्रम में 1997-2002 के दौरान 57734 मे.

वा. की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है। दूसरे ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा और नौवीं योजना प्रस्तावों के समेकन के साथ उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

कच्छ और बनासकांठा का औद्योगिक विकास

2609. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के प्रारम्भ में गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ;

(ख) इन जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से क्षेत्र उपलब्ध थे ;

(ग) इनमें सरकारी और निजी क्षेत्र का अनुपात कितना-कितना है ;

(घ) क्या ये जिले आठवीं योजनावधि के प्रारम्भ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर से बहुत पीछे चल रहे थे ; और

(ङ) सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा जिलों को राष्ट्रीय औद्योगिक मुख्य धारा में शामिल करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी तथा औद्योगिक वृद्धि के बारे में जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राष्ट्र की औद्योगिक मुख्य धारा में पिछड़े इलाकों को विकसित करके लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रों के त्वरित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1988 में विकास केन्द्र स्कीम की घोषणा की थी। गुजरात के लिए तीन विकास केन्द्रों अर्थात कच्छ जिले में गांधी धाम, बनासकांठा जिले में पालमपुर और भड़ोच जिल में वागरा का अनुमोदन किया गया इसके लिए 31 मार्च, 1997 तक केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 100 लाख रुपये, 100 लाख रुपये और 1000 लाख रुपये की धन राशि जारी कर दी गई है।

गुजरात सहित देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार अनेक विशेष रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रोजगार प्रदान करते हैं, वह हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन स्कीम। शहरी क्षेत्रों में दो गरीबी उन्मूलन स्कीमें चल रही हैं अर्थात नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भी रोजगार प्रदान करते हैं। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

Release of funds for development works in the North-East

2610. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a sum of Rs. 6100 crore was announced by the Prime Minister for development works in North-East;

(b) if so, how much funds have so far been released and what is the progress in this regard; and

(c) if not what do Government propose to do in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): The then Prime Minister issued